सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल का पता लगाना

629. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाने के लिये एक वर्ष अमरीका द्वारा छोड़े गये उपग्रह से उनका पता लगाने में सहायता मिली है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डी० पी० यादव): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Estimates of Indian Council of Social Welfare regarding hungry and blind children

630. SHRI RAJDEO SINGH:

DR. SARADISH ROY:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether according to the estimate of the Indian Council of Social Welfare nearly about 70 p.c. of the children in the country go to bed hungry;

(b) whether between 10,000 and 12,000 children go blind every year because of Vitamin 'A' deficiency; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) A large member of children belonging to the economically weaker sections of society are under nourished, though precise quantitative data are not available.

(b) Surveys conducted in the country have revealed that Vitamin 'A' deficiency among children is widespread. In its acute form this deficiency may lead to blindness. Possibly about 12,000 to 14,000 go blind every year due to this deficiency

(c) Government attach considerable importance to prevention of malnutrition amongst children and have launched the following programmes, which are proposed to be further expanded in the Fifth Plan —

Programme	Coverage	Financial outlay in the Fourth Plan
		Rs. in lakhs
(1) Prophylaxis against blindness due to Vitamin 'A' deficiency.	120 lakh beneficiaries	40 00
(2) Prophylaxis against nutritional anaemia among children and pregnent and nursing mothers.	180 lakh beneficiaries	166 00
(3) Supplementary feeding programmes for pre-school children and expectant and nursing mothers in urban slums and tribal areas.	40 lakh beneficiaries	5950 00
(4) Mid-day meals programmes for primary school children of 6 to 11 years.	130 lakhs (including 10 lakh pre-school children)	Food supplied free by CARI. Cost of transport and administrations meat by State Governments,
(5) Applied Nutrition Programme (mainly an educational effort to improve local diets through production, preservation and use of protective foods).	1181 Community Development Blocks	1000.00
(6) Composite Programme for women and pre-school children in areas not covered by the Applied Nutrition Programme.	314 Balwadis	290 00

Simultaneously, systematic efforts are being made to develop low-cost foods of the required nutritional value and consumer preference. As a further step in this direction, it is proposed to set up a Nutrition Development Corporation under the auspices of the Department of Food.

दिल्ली में वनस्पति की बिक्री के लिये जारी लाइसेंस देना

671 **श्री महादीपक सिंह शाक्य** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में वनस्पति के लाइसेंस दिये जाने में घोटाले की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या खुदरा व्यापारियों तथा वनस्पति विक्रेताओं से दिल्ली में वनस्पति की बिक्री हेतु प्रत्येक लाइसेंस के लिए शुल्क के रूप में 200 रुपये तथा कागज आदि के खर्च के लिए 5 रुपये वसूल किए गए हैं, और

(ग) क्या थोक विक्रेताओं ने इन लायसेंसों को मान्यता नहीं दी थी, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी पाये गए दिल्ली के सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). जनवरी, 1974 से पूर्व जिन व्यापारियों के पास 100 किलोग्राम तक वनस्पति का स्टाक रहता था उन्हें दिल्ली हाइड्रोजनेटेड वेजीटेबल आयल लाइसेंसिंग आदेश, 1967 के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त रखा गया था । क्योंकि इस सुविधा का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए यह सुविधा जनवरी, 1974 से समाप्त कर दी गई थी और सभी व्यापारियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई थी । इसके लिए प्रभार पहले जितना ही था अर्थात् लाइसेंस फीस 5 रुपये और प्रतिभूति जमा 200 रुपये ।

(ग) कम उपलब्धता होने के कारण थोक व्यापारी खुदरा व्यापारियों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थे लेकिन उनकी मांग सीमित मात्रा में पूरी की गई थी । दिल्ली के सिविल सप्लाईज विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रियों के आवासों को सजावट आदि पर किया गया खर्च

632 **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1973-74 में 31 जनवरी, 1974 तक केन्द्रीय उपमंत्रियों, राज्य मंत्रियों, मंत्रि-मंडल के स्तर के मंत्रियों, तथा प्रधान मंत्री के निवास-स्थानों में साज-सज्जा, बिजली तथा पानी की व्यवस्था पर पृथक-पृथक कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई , और

(ख) इस कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Central Assistance for development of Metropolitan-Cities

633 SHRI SAROJ MUKHERJEE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state.

(a) whether the Central Government has earmarked Rs. 250 crores for assistance for development of Metropolitan-Cities in different States; and

(b) if so, the amount sanctioned for each Metropolitan-City of different States, State-wise and City-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA). (a) A sum of Rs. 250 crores has been proposed in the Fifth Plan for extra financial assistance for metropolitan